

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3073
11.03.2026 को उत्तर देने के लिए
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025

†3073. श्री सेल्वाराज वी.:

श्री सुब्बारायण के.:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश का अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) संबंधी व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मात्र 0.6-0.7 प्रतिशत है और 'वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025' में भारत 38वें स्थान पर है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास संबंधी व्यय को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, जिससे कि भारत एक उच्च-तकनीकी (हाई-टेक) विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सके?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग): भारत का अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (जीईआरडी) एक दशक से अधिक तक जीडीपी का लगभग 0.6-0.7 प्रतिशत रहा है। पूर्ण रूप से देखा जाए तो, यह पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है और 2010-11 में 60,197 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 1,27,381 करोड़ रुपये हो गया है, जो दोगुने से भी अधिक है। हालांकि, जीडीपी की वृद्धि दर जीईआरडी की तुलना में कहीं अधिक रही है, इसलिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीईआरडी का मान कम बना हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की वर्तमान रैंकिंग 38वीं है, लेकिन 2015 में 81वें स्थान से 2025 में 38वें स्थान तक इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत को उच्च तकनीक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने अनुसंधान एवं विकास व्यय बढ़ाने हेतु कई उपाय किए हैं। इसमें शामिल है:

- वैज्ञानिक विभागों और अनुसंधान-उन्मुख कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन में क्रमिक वृद्धि।
- 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष का शुभारंभ।

- केंद्र सरकार द्वारा 14,000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान और गैर-सरकारी स्रोतों से अतिरिक्त धनराशि जुटाकर अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) की स्थापना।
- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (बजट परिव्यय: 6,003.65 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय अंतरविषयक साइबर-भौतिकी प्रणाली मिशन (बजट परिव्यय: 3,660 करोड़ रुपये), भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (बजट परिव्यय: 76,000 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन आदि जैसे राष्ट्रीय मिशनों का शुभारंभ।
- राष्ट्रीय अंतरविषयक साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करना ताकि सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।
- स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास, प्रोटोटाइपिंग, विस्तार और उद्योग संबंधों को सहायता देकर भारत की नवाचार-से-विनिर्माण श्रृंखला को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय नवाचार विकास और दोहन पहल (निधि), जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) कार्यक्रम, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडेक्स) और टाइड 2.0 (उद्यमियों का प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और विकास), का कार्यान्वयन, जिससे आयातित प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम की जा सके।
- भू-स्थानिक नीति 2022, अंतरिक्ष नीति 2023 और बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति 2024 जैसे सहायक नीतिगत ढाँचों की शुरुआत, जिनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालयों (टीटीओ), इन्क्यूबेशन केंद्रों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और संरचित लाइसेंसिंग मॉडल आदि के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों से नवाचारों के व्यावसायीकरण को मजबूत करना; आदि।
